दृष्टि The Vision

सामान्य अध्ययन (टेस्ट - XVI)

GENERAL STUDIES (Test - XVI)

मॉड्यूल - XVI / Module - XVI

DTVF/18(JS)–M–GS16

निर्धारित समयः तीन घंटे
Time allowed: Three Hours

अधिकतम अंकः 250
Maximum Marks: 250

नाम (Name): Anoop Meena

क्या आप इस बार मुख्य परीक्षा दे रहे हैं? हाँ ✓ नहीं

मोबाइल नं. (Mobile No.):

ई-मेल पता (E-mail address):

टेस्ट नं. एवं दिनांक (Test No. & Date): 16 | Aug 20, 2018

रोल नं. [यू.पी.एस.सी. (प्रा.) परीक्षा-2018] [Roll.No. UPSC (Pre) Exam-2018]:

0	8	3	4	4	6	9

परीक्षा का माध्यम (Medium of Exam.): हिंदी

विद्यार्थी के हस्ताक्षर (Student's Signature): [signature]

नोटः प्रश्न-पत्र के लिये विशिष्ट अनुदेश अंतिम पृष्ठ पर संलग्न हैं।

Evaluation Analysis

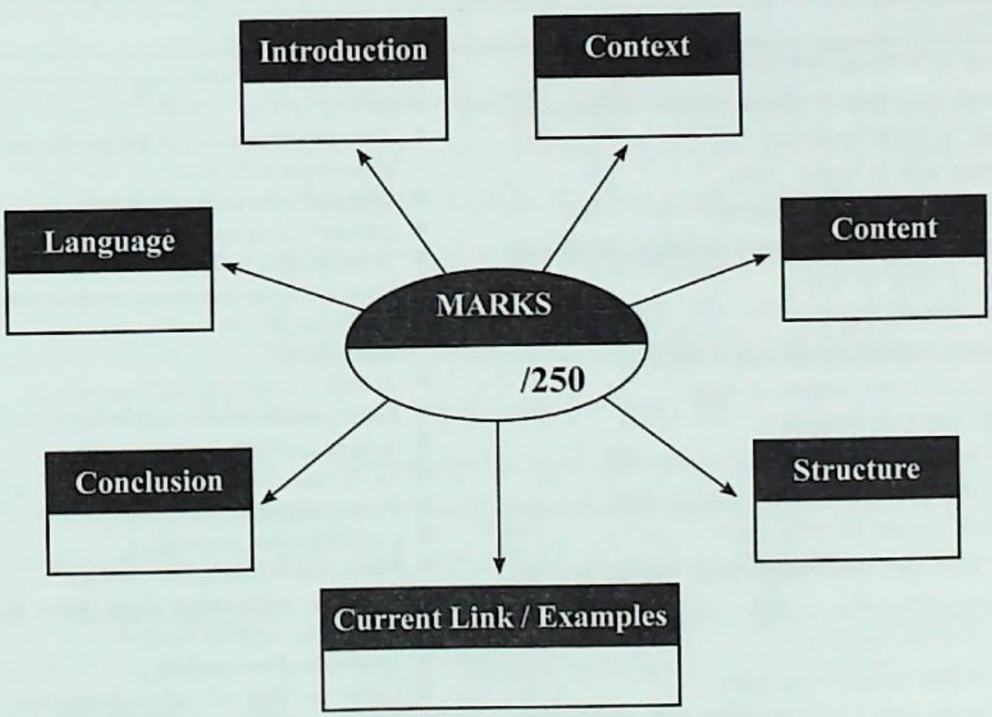

मूल्यांकनकर्त्ता (कोड तथा हस्ताक्षर)
Evaluator (Code & Signatures)

पुनरीक्षणकर्त्ता (कोड तथा हस्ताक्षर)
Reviewer (Code & Signatures)

मूल्यांकन की पद्धति

प्रिय अभ्यर्थियों,

आपकी उत्तर-पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करते हुए परीक्षक-समूह के सदस्य निम्नलिखित निर्देशों का ध्यान रखते हैं। आप भी इन्हें ध्यान से पढ़ें ताकि आप अपने प्राप्तांकों का तार्किक कारण समझ सकें।

परीक्षकों के लिये निर्देश

1. मूल्यांकन में अंकों का वही स्तर रखा जाना चाहिये जैसा संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के परीक्षकों द्वारा रखा जाता है।
2. सामान्य अध्ययन का जो उत्तर हर दृष्टिकोण से सटीक व उत्कृष्ट है; उसे अधिकतम 60% अंक दिये जाने चाहियें क्योंकि आयोग द्वारा किये जाने वाले मूल्यांकन में भी इससे अधिक अंक मिलना लगभग असंभव है। वैकल्पिक विषयों के उत्कृष्ट उत्तरों तथा श्रेष्ठतम निबंधों में अधिकतम 70% तक अंक दिये जा सकते हैं।
3. कृपया अंकों का वितरण निम्नलिखित तालिका के अनुसार करें-

Method of Evaluation

Dear Candidates,

While assessing your answer-scripts, the evaluators are required to follow the given instructions. You should also read them carefully to understand the logic behind the marks obtained by you in the tests.

Instructions for the Evaluators

1. The level of marks while evaluating the answers should be kept as per UPSC (Union Public Service Commission) standards as far as possible.
2. The answers of General Studies which are accurate and excellent from every perspective should be awarded a maximum of 60% marks as it is almost impossible to get more than that in actual UPSC examination. Excellent answers in optional subjects and the best written essays can be awarded a maximum of 70% marks.
3. Please assign the marks according to the following table-

उत्तर का स्तर (Standard of Answer)	सामान्य अध्ययन में अंक-स्तर (Marks Standard G.S.)	वैकल्पिक विषय तथा निबंध में अंक-स्तर (Marks Standard - Optional Subject and Essay)
उत्कृष्ट (Excellent)	51-60%	61-70%
बहुत अच्छा (Very Good)	41-50%	51-60%
अच्छा (Good)	31-40%	41-50%
औसत (Average)	21-30%	31-40%
कमजोर (Poor)	0-20%	0-30%

4. कृपया उत्तर में निम्नलिखित गुणों को विशेष प्रोत्साहन दें-
   - प्रश्न की सटीक समझ व उत्तर की व्यवस्थित रूपरेखा
   - संक्षिप्त, टू-द-पॉइंट लेखन शैली
   - प्रामाणिक तथ्यों का समुचित उपयोग
   - अधिकतम जरूरी बिंदुओं का समावेश
   - सरकारी दस्तावेज़ों (मंत्रालयों/आयोगों की रिपोर्ट्स, पॉलिसी पेपर्स आदि) के संदर्भों की चर्चा
   - प्रभावी भूमिका व निष्कर्ष
   - समकालीन घटनाओं/प्रसंगों को उत्तर से जोड़ना
   - दृष्टिकोण में संतुलन, समावेशन व गहराई
   - अच्छी, साफ-सुथरी हैंडराइटिंग
   - भाषा में प्रवाह
   - आवश्यकतानुसार डायग्राम्स, नक्शों आदि का प्रयोग
   - तकनीकी शब्दावली का सटीक उपयोग
   - सुंदर प्रस्तुति शैली (छोटे पैराग्राफ्स रखना, महत्त्वपूर्ण शब्दों को अंडरलाइन करना आदि)
   - विराम चिह्नों का समुचित प्रयोग
   - भाषा में वर्तनी व व्याकरण की शुद्धता
5. टॉपर्स के अनुभव बताते हैं कि उत्तर की विषयवस्तु अच्छी होने पर आयोग के परीक्षक शब्द-सीमा के थोड़े बहुत उल्लंघन पर अंक नहीं काटते हैं। कृपया आप भी इसी दृष्टिकोण के अनुसार अंक-निर्धारण करें।

4. Please devote special attention to the following qualities in an answer–
   - Accurate understanding of the question and systematic presentation of the answer
   - Crisp and to the point writing style
   - Adequate use of authentic facts
   - Inclusion of all the important points
   - Citing of relevant facts and figures from relevant official documents (Ministries /Commissions Reports, Policy Papers etc.)
   - Effective introduction and conclusion
   - Linking of current events and situations with the answer
   - Balance and depth in answer-writing
   - Legible and clean handwriting
   - Flow of language
   - Use of diagrams, maps etc
   - Precise use of technical terminology
   - Beautiful presentation style (small paragraphs, underlining important words etc.)
   - Proper use of punctuations
   - Correct spellings and right use of grammar
5. Experience of UPSC toppers also indicates that if the content of the answer is good, the UPSC examiners do not cut the marks on slight violations of the word-limit. Please award marks strictly according to the above-mentioned instructions.

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

1. भारत में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव एवं उनकी असुरक्षा से संबंधित विभिन्न कारकों की पहचान करें। साथ ही, सरकार द्वारा इसकी रोकथाम के लिये किये जाने वाले प्रयासों की चर्चा करते हुए सुधार के संबंध में अपना मत दें। (200 शब्द) 12.5

Identify the various factors related to discrimination and lack of security for women in India. Discuss the steps taken by the government in this regard and suggest measures for improvement. (200 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

वैश्विक वेतन सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार 27% महिलाएँ ही पुरुषों के सापेक्ष समान वेतन प्राप्त कर पाती हैं।

महिलाओं को विभिन्न प्रकार के भेदभाव व असुरक्षा का सामना करना पड़ता है जिसके निम्नलिखित कारक हैं:-

→ वेतन में असमानता तथा रोजगार के असमान अवसरों की कम उपलब्धता प्रायः मातृत्व लाभ व सांस्कृतिक कारकों से प्रेरित होती है।

→ 70% महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन असुरक्षा का सामना करना पड़ता है।

→ निर्णयन क्षमता की स्वतंत्रता न होने के कारण भी महिलाओं को इनका सामना करना पड़ता है।

→ सामाजिक अभिवृत्ति व पितृसत्तात्मक सोच (लैंगिक पूर्वाग्रह) के कारण भारत में महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य से संबंधित मामलों में द्वितीय लिंग की भूमिका के

Copyright – Drishti The Vision Foundation

रूप में देखा जाता है
→ बाल विवाह, कन्याभ्रूण हत्या जैसे कारक स्वयं ही भेदभाव के प्रतीक है
→ राजनीतिक संस्थाओं में निम्नभागीदारी कि नीतियों में लैंगिक संवेदनशीलता लाने में असम होती है इसलिए भी भेदभावों का सामना करना पड़ता है

इस संदर्भ में सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रयास किये गए है—
→ दहेज प्रथा विरोधी अधिनियम 1960 में द्वारा दहेज को गैर-कानूनी करार देना।
→ मातृत्व लाभ बिल 2018 का प्रस्ताव पारित करना।
→ 2013 में कार्यस्थल पर यौन हिंसा के निवारक के रूप में अधिनियम बनाना।
ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने हेतु शी-बॉक्स का निर्माण।
→ बाल विवाह रोधी अधिनियम।
→ बहुत्तीय जागरूकता व क्रियाकलापी योजनाएं चलायी जा रही है- जैसे - बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, स्टेंडअप इंडिया आदि।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

दृष्टि The Vision

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

इन प्रभावों का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है विशेषकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रमों का। लोगों में जागरूकता का स्तर बढ़ा है महिलाओं में शिक्षा व स्वास्थ्य का स्तर बढ़ा है मातृत्व मृत्यु दर घटी है।

यद्यपि हाल में बाल लिंगानुपात में कमी देखी गयी है।

समग्र रूप में विश्व बैंक के अनुसार यदि महिलाओं को सुरक्षापूर्ण वातावरण में समान आर्थिक अवसर दिये जाएं तो भारत की GDP में 27% वृद्धि हो सकती है।

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

2. बाल विवाह के मामले में भारत अभी भी विश्व के अग्रणी देशों में आता है, क्या इस कुप्रथा का कारण परंपरागत रूढ़िवादी सोच है? तर्क सहित विश्लेषण करें। साथ ही, इस संदर्भ में सरकार द्वारा किये गए प्रयासों की चर्चा करते हुए इसे रोकने के उपाय भी सुझायें। (200 शब्द) 12.5

India leads the countries in child marriages. Is the prevalent conservative mindset responsible for continuance of this evil practice? Analyse. Discuss the steps taken by the government and suggest measures to deal with it. (200 words) 12.5

अभी हालिया एक सर्वेक्षण में यह सामने आया है कि 82% महिलाओं ने यह स्वीकार किया है कि उनकी शादी 25 वर्ष से पहले हो गयी थी जबकि इनमें से लगभग 47% महिलाओं ने यह स्वीकार किया है कि उनका विवाह 18 वर्ष से पहले ही हो गया था।

भारत में यह समस्या पश्चिमी व उत्तर पश्चिमी भारत में मुख्य रूप से प्रचलित है।

इस परंपरा के पीछे प्राचीनकालीन व मध्यकालीन यह रूढ़िवादी सोच काम करती है कि महिलाओं की सुरक्षा का दायित्व जितनी जल्दी हो उसे हस्तांतरित कर दिया जाना चाहिए। इसके लिए वे अपने कुल व धर्म की इज्जत का हवाला देते हैं।

साथ ही वे लडकियों को आर्थिक भार समझते हैं अतः दहेज से बचने तथा

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे रचनात्मक कार्यों से बचने के लिए ऐसा करते है

परंतु रुढ़िवादी सोच तो एकमात्र कारण है अन्य कारणों में निर्धनता, सरकारी कानूनों का समय पर पालन न होना, लोगों में जागरूकता का अभाव आदि है

इस संदर्भ में सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रयास किये गए है।

→ बाल विवाह अधिनियम में महिलाओं की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गयी है साथ ही इसे संज्ञेय अपराध बनाया गया है

→ बाल विवाह केमुख्य कारक दहेज को नियंत्रित करने के लिए दहेज निवारण Act 1968 को अधिनियमित करना।

→ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे सृजनात्मक व जागरूक कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं तो वही सुकन्या समृद्धि योजना जैसे बीमा व वित्तीय प्रोत्साहन कार्यक्रम चलाये जा रहे है

इसे नियंत्रित करने हेतु उपाय निम्नलिखित है -

→ सबसे पहले जरूरी है लोगों की रुढ़िवादी सामाजिक अभिवृत्ति को बदलकर लैंगिक

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

समानता स्थापित करना। ताकि लड़कियों को आर्थिक भार न समझा जाए।

→ नागरिक समाज, सोशल मीडिया का प्रयोग करके ऐसी गतिविधियों को नियंत्रित करना।

→ शिक्षा - स्वास्थ्य के संदर्भ में कल्याणकारी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना तथा इनकी सामयिक निगरानी व मूल्यांकन करना।

बाल विवाह को रोककर हम सामाजिक सशक्तिकरण व लैंगिक न्याय की संवैधानिक भावना को साकार कर सकते हैं।

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

3. क्या मात्र मादक पेय पदार्थों के विक्रय स्थल पर नियंत्रण लगाने से इस समस्या का समाधान संभव है या इस मामले में कुछ अन्य प्रयास किये जाने की आवश्यकता है? विश्लेषण करें। (200 शब्द) 12.5

Can the issue of alcoholism be addressed only by controlling its sale or it requires other measures as well? Analyse. (200 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

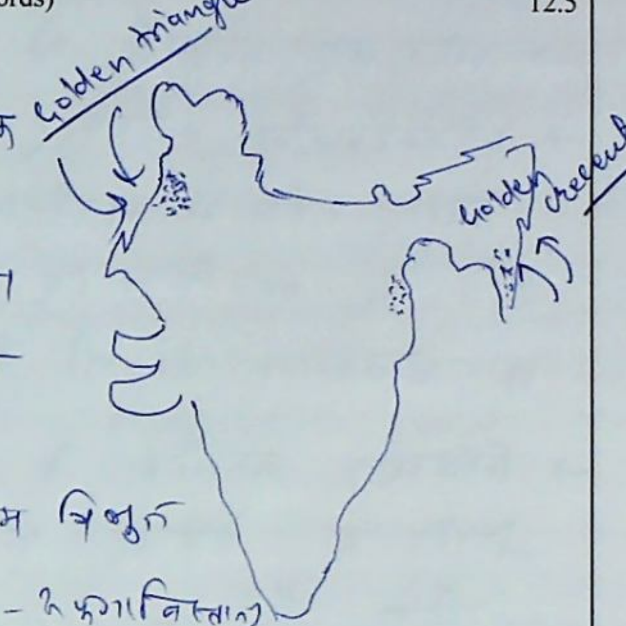

भारत में ड्रग व मादक
की समस्या मुख्य
रूप से पंजाब तथा
उत्तरी-पूर्वी भारत
में विद्यमान है।
पंजाब स्वर्णिम त्रिभुज
(ईरान - पाकिस्तान - अफगानिस्तान)
के समीप होने के कारण अत्यधिक संवेदनशील
क्षेत्र है।

वर्तमान में सरकार ने मादक पदार्थों की
समस्या का समाधान करने हेतु विक्रय स्थल
पर नियंत्रण करने का प्रयास किया है।
इसका लाभ यह है कि यह बेहतर
निगरानी व ट्रैकिंग करने में सहायक
होगा।

साथ ही विक्रय स्थलों की
जवाबदेहिता सुनिश्चित करने में सहायता

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

मिलेगी।

परंतु अन्य उपाय भी किये जाने की आवश्यकता है-

→ सीमापार आपूर्ति को नियंत्रित करना।

→ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियमित करना तथा वर्तमान लाइसेंस प्रणाली का उल्लंघन करने पर लाइसेंस रद्द करने के साथ दण्ड का प्रावधान का भी समावेशन करना।

→ निवारक उपायों के रूप में प्रभावित लोगों का बेहतर पुनर्वास करना चाहिए जैसे - रोजगार के अवसर, पर्याप्त शिक्षा व स्वास्थ्यगत सेवाएँ।

→ ~~अवैध~~ गैर - कानूनी तरीके से उत्पादक संयंत्रों को नियंत्रित करना चाहिए।

→ लोगों में जागरूकता का प्रचार करना विशेषकर महिलाओं में ताकि वे पारिवारिक आय को बचा सके।

→ पीड़ित लोगों की समग्र - समयपर स्वास्थ्य स्थिति की जाँचना।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

अतः हाल में पंजाब सरकार ने UNODC से MOU हस्ताक्षरित हुआ है। इसी तरह अग्रसक्रिय भूमिका निभाकर इस समस्या का समाधान किया जा सकता है।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

4. भारत में कुपोषण की समस्या भारत के सामाजिक व आर्थिक विकास के भविष्य पर आसन्न संकट के समान है। इस संकट के समाधान हेतु 'राष्ट्रीय पोषण मिशन' एवं 'जीरो हंगर कार्यक्रम' के महत्त्व को स्पष्ट करते हुए कुपोषण की समस्या के समाधान हेतु कुछ नवाचारी उपायों की चर्चा करें। (200 शब्द) 12.5

The issue of malnutrition endangers social and economic development of India. In this context, highlight the importance of 'National Nutrition Mission' and 'Zero Hunger Programme'. Also suggest some innovative measures to tackle the issue. (200 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को 119 देशों में से 100 वाँ स्थान प्राप्त हुआ है यह भारत को 31.4 का स्कोर प्रदान करके चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, एनीमिया, बालमृत्यु दर में निम्न स्तर प्रदान करता है

यह भारत के सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए कई रूपों में खतरा है सर्वप्रथम तो यह उत्पादक जनसंख्या (वर्तमान व भावी) को स्वास्थ्य रूप से दुर्बल बनाकर उसकी सामाजिक व आर्थिक उत्पादकता में ह्रास करता है

इसके अतिरिक्त यह सार्वजनिक संसाधनों पर अतिरिक्त भार उत्पन्न करके संसाधनों को कुपोषण, स्वच्छता आदि के क्षेत्रों में डायवर्ट करता है

इसके अतिरिक्त कुपोषण के

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

अंतरपीढ़ीगत होने की समस्या बनी रहती है विशेषकर जनजातीय समुदायों में।

इस संदर्भ में चलाए गए राष्ट्रीय पोषण मिशन व ज़ीरो हंगर कार्यक्रम अत्यधिक महत्वशाली सिद्ध हो सकते हैं क्योंकि ये कार्यक्रम विशिष्ट व स्पष्ट लक्ष्यों पर आधारित हैं ये मातृ-मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर व खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों की मात्रा को सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं।

इसके अतिरिक्त ये कार्यक्रम खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ पोषण सुरक्षा एवं माताओं की स्वास्थ्य देखभाल भी सुनिश्चित करते हैं ये जागरूकता का घटक भी समाहित किये हुए हैं।

कुपोषण की समस्या के नवाचारी समाधान निम्नलिखित है—

→ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में दाल, अंडे जैसे प्रोटीन व विटामिन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों से युक्त खाद्यों को शामिल करना।

→ मिड-डे-मील जैसी योजनाओं में फोर्टिफाइड फूड

दृष्टि The Vision
641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाषः 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेलः helpline@groupdrishti.com, वेबसाइटः www.drishtiIAS.com
फेसबुकः facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटरः twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

को शामिल करना।

→ जनजातीयों में जागरूकता बढ़ाना तथा उनकी नियमित स्वास्थ्य निगरानी व जागरूकता सुनिश्चित करना।

→ महिलाओं को शिशु को स्तनपान कराने के लिए जागरूक करने हेतु MAA जैसे कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन करना।

→ स्वच्छ भारत मिशन का प्रभावी क्रियान्वयन करना।

यदि हम कुपोषण की समस्या का समाधान कर लेंगे तो हम जनांकिकीय लाभांश को जनांकिकीय भार में बदलने से रोक सकेंगे। इसके लिए जरूरी है कि कुपोषण रोधी कार्यक्रमों की SDG के लक्ष्य 2 जीरो हंगर से संबद्धता हो।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

5. ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सुरक्षात्मक परिवेश उपलब्ध कराने के लिये लाया गया ट्रांसजेंडर (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2016 कितना उपयोगी साबित होगा? आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। (200 शब्द) 12.5

To what extent the Transgender (Protection of Rights) Bill, 2016 will be helpful in serving the interests of transgenders? Critically evaluate. (200 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

ट्रांसजेंडर समुदाय भारत में सर्वाधिक सुभेद्य वर्गों में से एक है उनके आर्थिक, सामाजिक जैसी बहुआयामी वंचनाओं का सामना करना पड़ता है

आय के अवसरों की सीमितता, पहचान प्रणाली का अभाव, सामाजिक रूप से कलंकित करना, परिवार से बहिष्कार, जैसी अनेक समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ता है

~~इसी~~ इन समस्याओं को संबोधित करने हेतु ट्रांसजेंडर (अधिकारों का संरक्षण) एक्ट 2016 लाया गया है।

इस विधेयक में ट्रांसजेंडरों की संख्या, स्थिति, वंचना आदि पर निगरानी रखने हेतु राष्ट्रीय व राज्य स्तरों पर आयोग की स्थापना का प्रावधान है

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

Copyright – Drishti The Vision Foundation

दृष्टि The Vision

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

बिना सहमति के पहचान को उजागर करने वाले अस्पताल या सार्वजनिक अधिकारियों हेतु दण्ड के प्रावधान है

यह बिल ट्रांसजेंडर समुदायों से संबंधित अपराधों को भी परिभाषित करता है जैसे - भीख मँगवाना, सार्वजनिक रूप से निजता का हनन करना।

इस बिल मे ट्रांसजेंडरों को औपचारिक क्षेत्र मे आरक्षण का प्रावधान भी शामिल है साथ ही इन्हे अपने परिवार वालों के साथ रहने का भी प्रावधान है

परंतु इस बिल की प्रमुख समस्या यह है कि यह ट्रांसजेंडरों तक ही सीमित है। अर्थात् यह संपूर्ण LGBT समुदाय को शामिल नही करता है

ट्रांसजेंडरों के खिलाफ होने वाले अपराधों को ट्रैक करने की भी व्यवस्था नही है

नाज फाउंडेशन के अनुसार इस बिल

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

में इस समुदाय को संपत्ति के अधिकार से वंचन
अपर्याप्त आरक्षण व वैधानिक संरक्षण होने
के कारण बिल की प्रभावशीलता कम होगी।

समग्र रूप से सभी हितधारक
(ट्रांसजेंडर समुदाय, सरकार, नागरिक
समाज) वर्तमान परिवर्तनशील परिस्थितियों
के अनुरूप प्रावधानों का समावेश करें।

दृष्टि The Vision
641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

7. बजट 2018-19 में चर्चा में रही आयुष्मान भारत योजना के अभिलक्षणों पर प्रकाश डालें। स्वास्थ्य क्षेत्रों में उपस्थित समस्याओं के निराकरण में सहायता प्रदान करने एवं गरीबों के स्वास्थ्य के लिये मील का पत्थर साबित होने के संदर्भ में इसका मूल्यांकन करें। (200 शब्द) 12.5

Highlight the features of the Ayushman Bharat Scheme unveiled in the Budget 2018-19. Evaluate it as a milestone for the health of the poor and a tool to resolve the problems of the health sector. (200 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

आयुष्मान भारत योजना दो धम्भों पर आधारित है-

1) हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर

2) राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना।

हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर स्वास्थ्य के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है इसमें निवारक उपाय जैसे टीकाकरण, स्वच्छता को अपनाने पर बल दिया जाएगा। (2.5 लाख)

नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम तृतीयक स्वास्थ्य क्षेत्र की बीमा आधारित योजना है इसमें 10 करोड़ परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख का बीमा / प्रति परिवार प्रदान करेगी। इससे भारत की लगभग 40% आबादी कवर होने की उम्मीद है। यह वर्तमान राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को प्रतिस्थापित करेगा

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

यह योजना वर्तमान में स्वास्थ्य क्षेत्र की अनेक समस्याओं का समाधान करने में सहायक सिद्ध हो सकती है —

भारत में लगभग 8% लोग ही सामाजिक सुरक्षा के दायरे में हैं अतः यह ~~लोगों~~ लगभग 40% भारतीयों तक बीमा कवर प्रदान करके उन्हें आर्थिक रूप से सुरक्षित करने का प्रयास करेगी।

भारत में बढ़ते आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडीचर को बीमा व वित्तीय सहायता के माध्यम से नियंत्रित करने का प्रयास करेगी।

यह समाज के वंचित वर्गों की स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुँच स्थापित करने में सहायक होगी।

इस योजना में निवारक दृष्टिकोण भी अपनाया गया है 1.5 लाख हेल्थ व वेलनेस सेंटर की स्थापना करके प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ किया जाएगा

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

निजी क्षेत्र के अस्पतालों के समकक्ष सेवायें सार्वजनिक क्षेत्र के अस्पतालों में उपलब्ध कराई जाएगी। अतः लोगों का आर्थिक शोषण रुकेगा।

अतः पर्याप्त वित्तीय संसाधन आवंटित करके, वर्तमान में संचालित बहुस्तरीय योजनाओं का समेकन करके इसको सफल बनाया जा सकता है।

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

8. ऊर्जा गंगा परियोजना के प्रमुख अभिलक्षणों पर प्रकाश डालते हुए इससे होने वाले लाभों का उल्लेख करें। (200 शब्द) 12.5

Highlight the key features of the Urja Ganga Project and list the benefits associated with it. (200 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

ऊर्जा गंगा परियोजना भारत के उत्तरप्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा व पश्चिम बंगाल में लागू की जा रही है।

गैस ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसकी नोडल एजेंसी है।

इस परियोजना के माध्यम से लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) का जनसामान्य तक वितरण करना है।

इसके द्वारा वितरित गैस का प्रयोग रसोई ईंधन के रूप में किया जाएगा। इसका अतिरिक्त उपयोग औद्योगिक विकास के लिए भी किया जा सकता है।

भविष्य में इस परियोजना को उत्तरपूर्वी भारत में भी विस्तारित किये जाने का प्रावधान है।

इस योजना के निम्नलिखित लाभ संभावित हैं:—

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

→ रसोई ईंधन के रूप में गैस की आपूर्ति से जीवाश्म ईंधन को प्रतिस्थापित किया जा सकेगा।

इससे पर्यावरणीय प्रदूषण को कम किया जा सकेगा। यह परियोजना भारत के INDC (पेरिस समझौते) को पूरा करने में सहायक होगी।

→ यह महिलाओं के सशक्तिकरण व लोगों के जीवन स्तर में उन्नयन हेतु भी आवश्यक है क्योंकि महिलाओं पर जीवाश्म ईंधन के संग्रहण की समस्या का भार समाप्त होगा।

यह अत्यधिक लागतप्रभावी कीमतों पर उपलब्ध होगी।

→ यह इंडोर प्रदूषण को कम करके श्वसन बीमारियों को कम करने में सहायता करेगी।

→ यह कृषि आधारित उत्तरी व पूर्वी राज्यों में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन करके भारत को गैस आधारित अर्थव्यवस्था।

दृष्टि The Vision
641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

अतः उचित क्रियान्वयन के माध्यम से यह परियोजना उत्तर-पूर्वी भारत में सामाजिक सशक्तिकरण व आर्थिक विकास का इंजन साबित हो सकती है।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

दृष्टि The Vision

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

10. 'भारत की चुनावी व्यवस्था में 'एक उम्मीदवार-एक सीट' का फॉर्मूला अपनाना लोकतांत्रिक सशक्तीकरण का महत्त्वपूर्ण कारक सिद्ध हो सकता है।' कथन का परीक्षण कीजिये। (200 शब्द) 12.5

'Adopting the scheme of 'One Candidate-One Seat' in election system of India will strengthen democracy.' Examine. (200 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

वर्तमान मे भारतीय मे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33 मे यह प्रावधान है कि एक प्रतिनिधि अधिकतम दो सीटों पर चुनाव लड़ सकता है।

यह प्रणाली वर्तमान मे लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए हानिकारक है क्योंकि यह जनविश्वास, सार्वजनिक संसाधन आदि को प्रभावित करती है।

विधि आयोग ने कहा कि जब देश मे एक मतदाता - एक मत का सिद्धांत प्रचलित है तो एक उम्मीदवार - एक सीट के सिद्धांत को भी अनुसरित करना चाहिए।

इस सिद्धांत के माध्यम से सार्वजनिक संसाधनों के अपव्यय को रोककर उसका जनकल्याणकारी कार्यों मे प्रयोग किया जा सकता है।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

वर्तमान व्यवस्था में एक साथ दो जगहों पर चुनाव लड़ने से एक सीट के मतदाताओं के साथ विश्वासघात होना तय होता है यह लोगों की लोकतंत्र में भागीदारी के लिए उदासीनता को बढ़ा सकता है

साथ ही यह प्रणाली मतदाताओं की समानता के सिद्धांत का भी उल्लंघन करते हुए वरीयता प्रदान करती है जबकि एक उम्मीदवार - एक सीट में वरीयता क्रम की दशा ही उत्पन्न नहीं होगी।

वर्तमान व्यवस्था से धनबल को बढ़ावा मिलता है क्योंकि अमीर लोग दो सीटों पर खड़े होकर चुनावी वित्तपोषण की सीमाओं का उल्लंघन करते है अत: इससे राजनीति का अपराधीकरण भी बढ़ता है जबकि एक उम्मीदवार - एक सीट के माध्यम से उम्मीदवार का ध्यान केवल एक ही सीट पर होगा।

अंतत: यह कहा जा सकता है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-33

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

के पुनर्विचार की आवश्यकता है क्योंकि
जनसंसाधन, जन विश्वास को संरक्षित रखने
के साथ-साथ चुनाव आयोग पर
कार्यभार कम करके पारदर्शी चुनाव
निर्धारित किये जा सकें।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

11. मानव तस्करी व्यक्ति के मानवाधिकार के हनन के साथ ही मानवता के क्षीण होने का प्रतीक भी है। भारत में संवैधानिक और वैधानिक स्तरों पर मानव तस्करी की रोकथाम के लिये किये गए प्रावधानों को इंगित करें और देश के प्रथम मानव तस्करी विधेयक, 2018 के औचित्य की परीक्षा करें। (200 शब्द) 12.5

Human trafficking violates the human rights and signals degeneration of humanity. Highlight the constitutional and legal provisions in India for prevention of human trafficking. Also examine the rationale of the Human Trafficking Bill, 2018. (200 words) 12.5

मानव तस्करी से तात्पर्य है इच्छा के विपरीत मानव का वस्तुवत उत्पीड़न करना।

गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक मानव तस्करी नेपाल, बांग्लादेश से होती है एवं यह पश्चिमी एशियाई देशों के लिए आपूर्ति का स्रोत बना है।

यह स्वतंत्रता, गरिमामय जीवन के अधिकार का उल्लंघन है यह शोषण आधारित व्यवस्था को बढ़ाता है समाज में घटती संवेदनशीलता को उद्घोषित करता है

भारतीय संविधान के प्रावधानों में मानव तस्करी को अवैध घोषित किया गया है जैसे - अनुच्छेद 23 में मानव

Copyright - Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

दुर्व्यापार को असंवैधानिक बताया गया है अनुच्छेद 21 में गरिमामय जीवन जीना भी अप्रत्यक्ष रूप से तस्करी को नियंत्रित करने हेतु निर्देशित किया गया है

यह अनुच्छेद 19 (स्वतंत्र विचरण) का भी उल्लंघन करता है साथ ही अनुच्छेद 15, 16 (वर्ग, लिंग के आधार पर भेदभाव) को भी नियंत्रित करता है

उज्जवला योजना के माध्यम से तस्करी से पीड़ित महिलाओं के पुनर्वास की व्यवस्था है

मानव तस्करी विधेयक 2018 एक नियामक व पुनर्वास प्रणाली की स्थापना करता है

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

12. आज भारत 'ई. गवर्नेंस' से आगे 'एम. गवर्नेंस' की ओर तेजी से बढ़ रहा है फिर भी, कई बार समाज के निचले पायदान पर बैठे व्यक्ति को 'गुड गवर्नेंस' का लाभ नहीं मिल पाता। स्पष्ट कीजिये। 12.5 (200 शब्द)

India is moving towards 'm-governance' from 'e-governance', yet many a time the people in the lowest rungs of society fail to get the benefits of good governance. Discuss. 12.5 (200 words)

ई-गवर्नेंस से तात्पर्य है सेवाओं का इलेक्ट्रॉनिक वितरण। अर्थात सूचनाओं का प्रभावी-अबाधित रूप से वितरण करना।

एम. गवर्नेंस की अवधारणा शासन में जनसहभागिता को बढ़ाने से सम्बन्धित है विधिक संवीक्षा (लेजिस्लेशन स्क्रूटनी), सोशल मीडिया, ग्रीन पेपर रिलीज करके, MyGov एप के माध्यम से जनसहभागिता को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।

ई-गवर्नेंस व एम गवर्नेंस सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों की व्यापकता व अधिक सामाजिक स्वीकार्यता के साथ बेहतर क्रियान्वयन मे भी भूमिका निभाते हैं।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

परंतु कई बार यह देखा गया है कि समाज के निचले लोगों को गुड गवर्नेंस का लाभ नहीं मिल पाता है इससे सेवाओं के प्रभावी वितरण की प्रक्रिया बाधित होती है

समाज में व्याप्त डिजिटल डिवाइड (इंटरनेट की असमान पहुँच) इसका एक प्रमुख कारण है साथ ही लोगों को सरकारी पहलों की पर्याप्त रूप से जानकारी नहीं होने के कारण वे इनके लाभों से वंचित रह जाते हैं।

सिटीजन चार्टर जैसी जवाबदेह प्रणाली का अभाव भी गुड गवर्नेंस में ~~बाध~~ लोगों की भागीदारी को बाधित करता है इसके अतिरिक्त राजनीतिक ~~निर्णय~~ संस्थाओं जैसे पंचायतों में निम्न भागीदारी (विशेषकर जनजातीय व सुदूरवर्ती क्षेत्रों के लोगों की) भी गुड गवर्नेंस के लाभों से वंचित करती है

परंतु वर्तमान सोशल मीडिया

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

के माध्यम से एक तरफ जागरूकता अभियान चलाये जा रहे है तो भारतनेट योजना के माध्यम से डिजिटल डिवाइड को सीमित करने का प्रयास किया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज मिशन के माध्यम से पंचायतों का सशक्तिकरण करने का प्रयास किया जा रहा है।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

13. चुनावों में राज्य वित्तीयन भारतीय राजनैतिक व्यवस्था को बेहतर कार्य निष्पादन के लिये प्रेरित कर सकता है। चुनावों में राज्य वित्तीयन के औचित्य को स्पष्ट करते हुए इस व्यवस्था के महत्त्वपूर्ण लाभों की चर्चा करें। (200 शब्द) 12.5

State Funding of Elections can help improve the Indian political system. Explain the significance of State Funding of Elections and illustrate its benefits. (200 words) 12.5

कृपया इस स्थान कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अनुसार भारत में चुनावी वित्तपोषण का 70% भाग नकद व अज्ञात स्रोतों से प्राप्त होता है।

इसलिए इंद्रजीत गुप्ता समिति, संवैधानिक समीक्षा आयोग ने चुनावी वित्तपोषण की वर्तमान अपारदर्शी व्यवस्था को नियमित करने के लिए राज्य द्वारा वित्तपोषण का समर्थन किया।

राज्य द्वारा वित्तपोषण का औचित्य इस रूप में है कि यह चुनावी संस्कृति में पारदर्शिता व जवाबदेहिता का संचरण करने में सहायता करेगी।

राज्य द्वारा वित्तपोषण करने का लाभ यह होगा कि राजनीतिक दलों व कार्पोरेट संगठनों का क्रोनी कैपिटलिज्म

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

का सम्बन्ध नियमित किया जा सकेगा।

साथ ही चूंकि वित्तीयन राज्य द्वारा किया जाएगा इसलिए राज्य द्वारा राजनीतिक दलों पर कुछ प्रतिबंध भी लगाये जायेंगे। इससे राजनीतिक दलों में भी आंतरिक लोकतंत्र बढ़ेगा क्योंकि उनकी आय के स्रोतों पर से निर्भरता समाप्त होगी।

वर्तमान में यह देखने में मिलता है कि राजनीतिक दल कार्पोरेट संगठनों के पक्ष में नीतियाँ निर्माण करके लोकतंत्र को विकृत करने का प्रयास करते हैं। अतः जनहितकारी नीतियाँ अवरुद्ध होती हैं जबकि राज्य के द्वारा वित्तीयन से बाह्य दबाव समाप्त होने से समावेशी नीति बनेंगी।

भारत में धनबल व बाहुबल, राजनीति के अपराधीकरण को नियंत्रित करके सत्यनिष्ठ व उच्च चरित्र वाले लोगों को राजनीति में शामिल करने में यह महती भूमिका निभा सकता है।

दृष्टि The Vision
641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this

परंतु इसका नुकसान यह है कि यह सार्वजनिक धन का दायवर्जन करेगा, छोटे दलों की अपेक्षा राष्ट्रीय व स्थापित दल को अधिक लाभ मिलेगा आदि।

समग्र रूप में वर्तमान में वित्तीयन के नियमों का दृढ़ क्रियान्वयन करके, चुनावी बांड योजना को लागू करके, बैंक में चंदा लेने को अनिवार्य बनाकर, राजनीतिक दलों को RTI के दायरे में लाकर चुनावी वित्तपोषण में पारदर्शिता बढ़ायी जा सकती है।

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

14. भारत जैसे लोकतंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेहिता सुनिश्चित करने में 'नागरिक घोषणा-पत्र' एक उत्तम साधन बन सकता है। इस संदर्भ में किये गए प्रयासों की एक रूपरेखा प्रस्तुत कीजिये। 12.5 (200 शब्द)

'Citizen Charter' can become a perfect tool to ensure transparency and accountability in a democracy like India. Highlight the steps taken in this regard. (200 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

नागरिक घोषणा पत्र की अवधारणा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉन मेयर ने प्रतिपादित की थी।

सिटीजन चार्टर मे यह वर्णित होता है कि क्या-क्या सेवाएँ किन-किन लाभार्थियों को प्राप्त होगी। साथ ही शिकायत निवारण तंत्र का भी प्रावधान है।

सिटीजन चार्टर पारदर्शिता व जवाबदेहिता कई रूपों में सुनिश्चित करता है इसमें पर्याप्त सूचनाओं का वर्णन होने से स्वच्छता होती है अतः भ्रष्टाचार व गोपनीयता की संस्कृति पर अंकुश लगाता है

यदि नागरिकों को सिटीजन चार्टर में वर्णित सेवाओं की समय पर उपलब्धता नहीं होती है तो समय-समय पर शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है,

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

यह कर्मचारी में जनहित व सेवाओं के बेहतर वितरण की भावना सुनिश्चित करता है।

सरकार के द्वारा गठित द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने निम्नलिखित प्रयास किए हैं।

→ भारत में सिटीजन चार्टर का सेवोत्तम मॉडल प्रस्तुत करना। यह सिटीजन चार्टर का भारतीय संस्करण है इसमें सेवाओं की वर्गीकरण के साथ-साथ मध्यावधि समीक्षा व अद्यतन को शामिल किया गया है

→ सभी सरकारी विभागों व मंत्रालयों के लिए सिटीजन चार्टर को लागू करने के निर्देश भी दिये हैं

→ संगठनों के आंतरिक पुनर्गठन, सभी हितधारकों से वार्ता करके सेवाएँ शामिल करना, शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना करना, समय-समय पर उपयोगकर्ताओं के द्वारा फीडबैक प्राप्त करने जैसे प्रयासों का भी समर्थन किया है

दृष्टि The Vision
641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

परंतु भारत में परिवर्तन विरोधी व्यवस्था, विधिक समर्थन के अभाव, लोगों में जागरूकता का न होना, समय-समय पर अद्यतन न करने के कारण अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा है।

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

15. केंद्र सरकार द्वारा विगत दिनों शुरू किये गए 'एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम' के बारे में आप क्या जानते हैं? क्या यह पहल बेहतर शासन और सहकारी संघवाद को और मजबूत कर सकता है? चर्चा कीजिये। (200 शब्द) 12.5

What do you know about the 'Aspirational Districts Programme' launched by the Central Government? Can this initiative strengthen good governance and cooperative federalism? Discuss. (200 words) 12.5

केंद्र सरकार ने नीति आयोग के नेतृत्व में एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का शुभारंभ किया है। इनमें देश के 115 जिले शामिल है।

ये जिले विभिन्न मानकों जैसे पेयजल, स्वच्छता, पोषण, रसोई ईंधन, विद्युत, कनेक्टिविटी में सामान्य जिलो से सापेक्ष रूप से पिछड़े है।

यह पहल बेहतर शासन व सहकारी संघवाद की स्थापना करने मे महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित रूप में निभायेगी —

→ यह विकासात्मक गतिविधियो में जनसहभागिता को ~~प्राप्त~~ बढ़ायेगी। जैसे स्वच्छ भारत मिशन का क्रियान्वयन।

इनसे प्राप्त फीडबैक के माध्यम से कार्यक्रम में आवश्यक संशोधन करना

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

एवं आवधिक मूल्यांकन निष्पादित करना।

→ यह कार्यक्रम शासन के तीनों स्तरों को वित्तीय व नियम निर्माण के लिए प्राधिकृत करके सहकारी संघवाद को सुनिश्चित करती है। इस कार्यक्रम का नोडल अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट होगा जो संबंधित क्षेत्र के सांसद को सलाह देगा।

→ यह साक्ष्याधारित व बॉटम अप उपागम पर आधारित है। साथ ही इसमें नागरिक समाज के द्वारा सामाजिक लेखा परीक्षा के पहलू को शामिल करके गुड गवर्नेंस की अवधारणा को अपनाया गया है।

→ इसमें केंद्रीय व राज्य के कल्याणकारी कार्यक्रमों को एकीकृत रूप से संचालित करके भी सहयोगी संघवाद की अवधारणा को मजबूत करने का कार्य किया है।

दृष्टि The Vision
641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

समग्र रूप से यह कार्यक्रम यदि उचित जनसहभागिता व उत्तरदायित्व की भावना से क्रियान्वित किया गया तो यह बेहतर शासन व सहकारी संघवाद का बेहतर उदाहरण बन सकता है।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

16. राष्ट्रमंडल मंच पर भारत की स्थिति पहले से कहीं अधिक मज़बूत हुई है। इस परिप्रेक्ष्य में यह मंच भारत के लिये कितना हितकर होगा? चर्चा कीजिये। (200 शब्द) 12.5

India's stature at the Commonwealth has strengthened. To what extent this forum can be favourable for India? Discuss. (200 words) 12.5

राष्ट्रमंडल में वे देश शामिल हैं जिनका औपनिवेशक काल में ब्रिटेन से संबंध रहा हो।

राष्ट्रमंडल के प्रमुख देशों जैसे- ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका से भारत के बेहतर आर्थिक व राजनीतिक संबंध है।

अभी हाल में लंदन में हुए राष्ट्रमंडल सम्मेलन ने विभिन्न देशों के साथ कई समझौते किये जैसे- इनोवेशन फॉर ग्रोथ कॉमनवेल्थ की स्थापना, आदि।

यह मंच भारत के लिए कई रूपों में लाभकारी सिद्ध हो सकता है-

→ यह मंच भारत की NSG व UNSC में सदस्यता के लिए पर्याप्त समर्थन देने में भूमिका निभा सकता है

Copyright – Drishti The Vision Foundation

दृष्टि The Vision

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

→ इसमें अधिकांश देश एशिया - अफ्रीका महाद्वीप से हैं। अतः यह वार्ता का के अतिरिक्त मंच उपलब्ध कराकर विभिन्न मुद्दों के समाधान में सहायक हो सकता है।

साथ ही इसके सदस्य देश भारत के लिए बाजार की आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं।

→ राष्ट्रमंडल में ब्रिटेन व ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देश भी शामिल हैं जिनसे प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के साथ-साथ निवेश आकर्षित करने में सहायता मिलेगी।

→ भारत की सेवा व्यापार में प्रधानता है। जबकि ब्रिटेन व ऑस्ट्रेलिया जनांकिकीय संक्रमण के चतुर्थ चरण में है अतः उनकी कुशल मानव संसाधन की आवश्यकता की पूर्ति करने में भारत महती भूमिका निभा सकता है।

कृपया इस स्थान कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

समग्र रूप से कहा जाए तो राष्ट्रमंडल भारत को विश्व में बढ़ती संरक्षणवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने में सहायता करने के साथ-साथ निवेश, प्रौद्योगिकी व बाजार सुविधा प्राप्त करने में सहायता कर सकता है।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

17. क्वाड (QUAD) में भागीदारी भारत को अपने ही प्रतिस्पर्द्धी पड़ोसी के विरुद्ध एक मज़बूत आधार प्रदान कर सकता है। लेकिन इस संदर्भ में भारत को सावधानी बरतनी भी आवश्यक है। कथन की पुष्टि कीजिये। (200 शब्द) 12.5

The QUAD can provide India a strong backing against its hostile neighbor, but India needs to be equally cautious. Substantiate. (200 words) 12.5

क्वाड में भारत, अमेरीका, जापान व ऑस्ट्रेलिया शामिल है। इसने संस्थानिक रूप धारण न करते हुए केवल वैचारिक स्वरूप प्राप्त किया है।

क्वाड का उद्देश्य मुक्त समुद्री संचलन, सामुहिक सुरक्षा व नियम आधारित विश्व व्यवस्था का समर्थन करना है।

यह भारत को अनेक रूपों में मजबूत आधार प्रदान करता है यह चीन की बढ़ती आक्रामकता विशेषकर दक्षिण चीन सागर व हिंद महासागर को नियंत्रित व प्रतिसंतुलित करने में भागीदारी निभा सकता है।

इसके सदस्य देशों ने विभिन्न सुरक्षात्मक मुद्दों पर भारत का समर्थन

कृपया इस स्थान कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

दृष्टि The Vision
641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

Copyright – Drishti The Vision Foundation

क्रिया है जैसे डोकलाम विवाद के समय जापान ने भारत के मत का समर्थन किया था तो दक्षिण चीन सागर विवाद पर भारत ने जापान का समर्थन किया था।

जापान - अमेरिका ने पैसिफिक क्षेत्र को इंडो पैसिफिक नाम देकर भारत के बढ़ते कद को समर्थित किया है

आतंकवाद पर चीन के पाकिस्तान को समर्थन तथा चीन - रूस - पाकिस्तान की उभरती धुरी के मद्देनजर इसका महत्त्व स्वतः ही बढ़ जाता है

परंतु भारत को सावधानी बरतनी चाहिए। भारत को यह प्रयास करना चाहिए कि चीन इसे चीन विरोधी तथा रूस इसे रूस विरोधी सैन्य संगठन के रूप में न देखे। इसलिए ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन पर सतत सहयोग के द्वारा विश्वास बहाली करनी चाहिए।

अभी क्वाड का चार्टर, सिद्धांत आदि घोषित व स्थापित नहीं हुये

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation
कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)
कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

है अतः भारत को आत्मसंयमित रहते हुए दूरदर्शी नीति अपनानी चाहिए।

सुदूर प्रशांत क्षेत्र की अपेक्षा भारत के हित हिंद महासागर क्षेत्र में है। अतः भारत को यहाँ पर चीन को संतुलित करते हुए अपना ध्यान आर्थिक विकास व पड़ोसियों पर केंद्रित करना चाहिए।

समग्र रूप से भारत को क्वाड तथा चीन के मध्य संतुलन स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए।

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)
कृपया इस स्थान कुछ न लिखें। (Please don't w anything in this
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

18. भारत क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (RCEP) के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करता है। लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में इसे स्वहित का ध्यान भी रखना होगा। कथन का परीक्षण कीजिये। (200 शब्द) 12.5

India's commitment towards Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) should ideally be balanced with its self-interest. Examine. (200 words) 12.5

RCEP में आसियान के 10 देशों के अलावा भारत, चीन, द० कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड शामिल है यह एक क्षेत्रीय मुक्त व्यापार समझौता है।

इस समझौते के अनेक प्रावधानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करता है भारत वस्तु व सेवाओं के मुक्त व्यापार के संचलन का समर्थक रहा है वह इन समझौते के प्रमुख प्रावधानों के अनुरूप टैरिफ व नॉन टैरिफ प्रतिबंधों को समाप्त करते हेतु समर्थक रहा है।

साथ ही बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण का समर्थन भी करता है

परंतु भारत को अपने स्वहित का भी ध्यान रखना चाहिए —

→ सर्वप्रथम तो भारत ने सेवा व्यापार (Mode-4) के संदर्भ में प्रोफेशनलों का

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

मुक्त संचलन का समर्थन किया है।

→ भारत को सभी देशों के साथ वस्तुओं के मुक्त आवागमन की अनुमति देनी चाहिए। परंतु चीन के प्रति संतुलित दृष्टिकोण अपनाकर कदम उठाना चाहिए। क्योंकि RCEP एक तरीके से चीन के साथ अप्रत्यक्ष FTA की भाँति है।

अतः इससे भारतीय कृषि व विनिर्माण उद्योग को क्षति होने की संभावना बनी रहती है।

→ इसके साथ ही भारत द्वारा विभिन्न भागीदारी देशों विशेषकर चीन द्वारा जेनेरिक दवा व कृषि उत्पादों पर लगाये जाने वाले नॉन टैरिफ प्रतिबंधों को भी संबोधित करना चाहिए।

→ भारत को <u>ट्रिप्स प्लस</u> जैसे बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण मुद्दों पर स्वहितों से समझौता नहीं करना चाहिए।

इन मुद्दों को ध्यान में रखकर भारत RCEP को स्वतः हितों के

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

अनुरूप ढालने का प्रयास करना चाहिए।

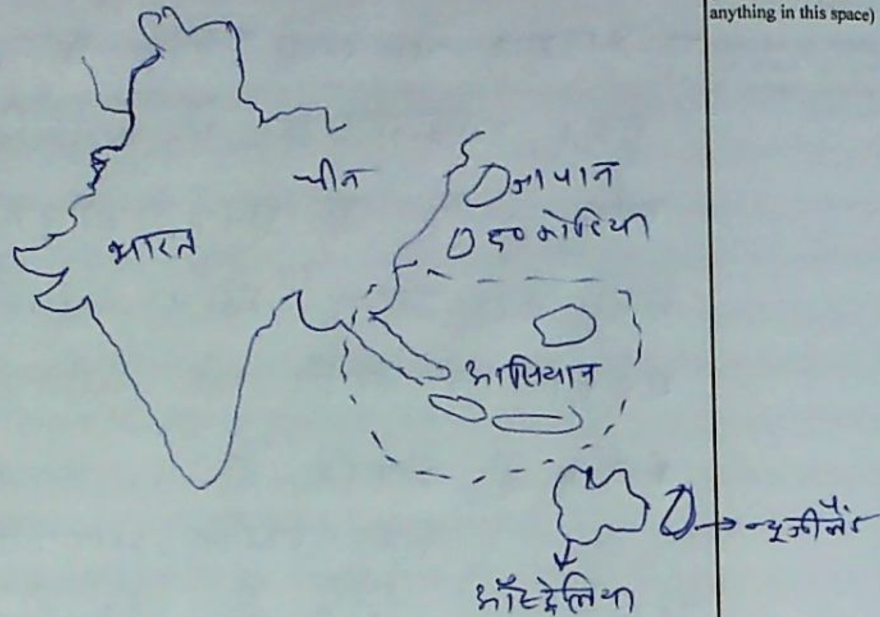

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

19. हाल के समय में देखा गया है कि भारत ने विभिन्न देशों के साथ व्यापारिक और सामरिक संबंध प्रगाढ़ करने के साथ सांस्कृतिक संबंध को भी अग्रिम पंक्ति में रखा है। इस विचार को केंद्र में रखकर भारत की बदलती विदेश नीति पर एक टिप्पणी लिखिये। (200 शब्द) 12.5

While deepening the trade and strategic ties with other countries India is also keeping the cultural dimension at the forefront. In this context, comment on the evolving foreign policy of India. (200 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

भारत का पारंपरिक रूप से ध्यान व्यापारिक व सामरिक संबंधों पर रहा है परंतु हालिया ऐसे परिवर्तन देखने को मिले है कि इसमें सांस्कृतिक पहलुओं के समावेशन भी किया जाने लगा है

इससे विदेश नीति मे विविधीकरण के साथ-साथ गतिशीलता भी आयी है एवं सॉफ्ट पावर के साथ-साथ स्मार्ट पावर का भी समावेश हुआ है।

पूर्वी एशिया व दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ एक्ट ईस्ट नीति के अंतर्गत बौद्ध कूटनीति इसका प्रमुख आयाम है नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध भिक्षुओं को अध्ययन की सुविधा प्रदान करता।

यही नहीं पश्चिमी एशिया से भारत में पर्याप्त संप्रेषण, निवेश प्राप्त होने के साथ-साथ भारतीय ऊर्जा का

Copyright – Drishti The Vision Foundation

लगभग 2/3 भाग आयात किया जाता है परंतु यहाँ भारतीय डायस्पोरा के माध्यम से सांस्कृतिक संबंध भी जुड़े हुए है। विशेषकर संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, में पाया यहाँ मंदिरों के निर्माण, भारतीय उत्सवों को मनाया जाने लगा है

भारतीय पड़ोसी देश नेपाल, भूटान से सामरिक रूप से एक तरफ क्रमशः 1950 व 2007 की मित्रता संधियाँ है तो वहीं नेपाल से लगभग तीस लाख लोग भारत में रोजगार प्राप्त करते है। नेपाल व भारत के बिहार - उत्तरप्रदेश राज्यों के लोगों से वैवाहिक संबंध स्थापित हुये है

सांस्कृतिक पहलू का अन्य पक्ष यह भी है कि हाल ही विदेशों में भारत के कार्यों का समर्थन मिलता है जैसे - भारतीय प्रवासी दिवस के तहत विदेशी भारत मूल के उद्यमी, राजनीतिज्ञ व वैज्ञानिकों को आमंत्रित करना।

भारत को जानो कार्यक्रम

दृष्टि The Vision
641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

, स्टैंडअप इंडिया जैसे कार्यक्रम इसी पक्ष का समर्थन करते हैं इससे भारत को निवेश, संप्रेषण, समर्थन (जैसा कि भारत-अमेरिका सिविल-न्यूक्लियर समझौते के समय देखा गया था) जैसे लाभ मिलते हैं।

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष: 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

20. आने वाले वर्षों में चीन की बढ़ती हठधर्मिता भारत की विदेश नीति के लिये बड़ी चुनौती बन सकती है। ऐसे में, भारत को अपने पड़ोसी के साथ कूटनीतिक संपर्क के अतिरिक्त जनसंपर्क विस्तार पर भी ध्यान देना सही कदम होगा। चर्चा कीजिये। (200 शब्द) 12.5

An assertive China poses a major challenge for India's foreign policy. While improving its diplomatic ties India should also expand the people to people engagement. Discuss. (200 words) 12.5

भारत व चीनी संबंधों को प्राय: प्रतिद्वंद्वी - सहयोगी - प्रतिस्पर्धी जैसे शब्दों के समावेशित स्वरूप से समझा जा सकता है।

यद्यपि विश्व व्यापार संगठन, ब्रिक्स, SCO जैसे संगठनों में भारत-चीन का सहयोग है परंतु बहुतायत मुद्दों पर वैचारिक भिन्नता भी है। चीन की बढ़ती आक्रामकता के कारण इनमें तीव्रता देखने को मिली है—

→ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद व परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समूह में भारत की सदस्यता बाधित करना।

→ चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (कश्मीर) के माध्यम से भारत की संप्रभुता व अखंडता की अनदेखा करना। एवं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की घेराबंदी नीति से भारत को घेरना।

→ दक्षिण चीन सागर में बढ़ती आक्रामकता से नियम आधारित विश्व व्यवस्था को चुनौती।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

→ डोकलाम जैसे गतिरोध व सीमा विवादों पर बढ़ती आक्रामकता के साथ ब्रह्मपुत्र नदी पर बाँध का जल को डायवर्ट करना इसके साथ ही पाकिस्तान का आतंकवाद के मुद्दे पर समर्थन।

अतः इन मुद्दों को देखते भारत को गुजराल डॉक्ट्रिन व नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत अपने पड़ोसियों से संबंध सुधारने चाहिए।

इसके लिए SAARC जैसे संगठन को पुनर्जीवित करने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ ट्रैक-1 के साथ-साथ ट्रैक-2 कूटनीति (गैर सरकारी लोग, मीडिया आदि) भी अपनानी चाहिए।

अधूरे प्रोजेक्ट्स जैसे कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, BBIN नेटवर्क, नेपाल में जलविद्युत परियोजना, श्रीलंका के साथ तमिल व मछुआरों का विवादों का समाधान करना चाहिए।

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें (Please don't write anything in this space)

Copyright – Drishti The Vision Foundation

दृष्टि The Vision

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

भारतीय पड़ोसियों के मध्य कनेक्टिविटी हेतु कदम बढ़ाने चाहिए। लोगों के मध्य संपर्क बढ़ाने हेतु संचार उपग्रह, पर्यटन - वीजा प्रणाली को सरल करने जैसे प्रयास करने चाहिए।

इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित करना चाहिए की पड़ोसी देश भी भारतीय हितों का ध्यान रखते हुए चीन के प्रभाव को संयमित करें।

Feedback

Questions ....

Model Answer & Answer Structure ....

Evaluation ....

Staff ....

Copyright – Drishti The Vision Foundation

प्रश्न-पत्र के लिये विशिष्ट अनुदेश

कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें:

इसमें बीस प्रश्न हैं तथा हिन्दी और अंग्रेज़ी दोनों में छपे हैं।

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिये गए हैं।

प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहियें जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिये। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।

प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिये।

प्रश्न-सह-उत्तर-पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिये।

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instruction carefully before attempting questions:

*There are **TWENTY** questions printed both in **HINDI** and in **ENGLISH**.*

All the questions are compulsory.

The number of marks carried by a question is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.

Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

समग्र मूल्यांकन

(Overall Evaluation)

Copyright – Drishti The Vision Foundation